of police station Hauz Khas and Vasant Kunj is as under:

Crime	P.S. Hauz Khas	P.S. Vasant Kunj
Theft	137	98
Burglary	18	12

(d) The listed criminals and suspects are being throughly interrograted. Door to door survey has been conducted for the verification of domestic servants. Patrolling has been intensified in the area. The resients are being apprised with the security measures to the taken by them. Neighbourhood watch scheme has been started in these areas. Extra pickets are being laid during night hours in the crime infested areas.

बिहार के मधुबनी जिले में कार्यरथ प्लाइवुड कारखाने

*218. **श्री राम देव भंडारी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के मधुबन जिला में प्लाईवुड के कितने कारखाने कार्यरत हैं;

(ख) क्या उपरोक्त वर्णित कारखानों की संख्या इस जिले में वृक्षों की संख्या की तुलना में काफी ज्यादा है;

(ग) क्या इस कारखानों के कारण वृक्षों को बड़ी तेजी से काटा जा रहा है जिससे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की शीघ्र जांच कराकर वृक्षों का कटाव रोकने के लिए बड़ी पैमाने पर कारखानों को बन्द करेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

राजकोट में उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना

219. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजकोट में उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एककों के विकास की व्यापक संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव): (क) जी नहीं।

(ख) स (ग) गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एककों के विकास की संभावना है। खाध प्रसंस्करण उद्योग के निवेश को प्रोत्साहन देने के विचार से सरकार ने अपनी नीतियों को उदार बनाया है और अल्कोहल पेयों की किण्वन और आसवन, चीनी व लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है। सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु विदेशी इक्विटी निवेश की अनुमति भी देती है। विदेशी प्रोद्यौगिकी करारों का उदारीकरण व खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए वित्तीय राहतों जैसे कई अन्य प्रोत्साहन पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। मंत्रालय कुछ योजना स्कीमें भी चला रहा है जिनके तहत संयुक्त उद्यम, सहायता प्राप्त/सहकारी क्षेत्रों या निजी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एककों को स्थापना/उन्नयन के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त हुए प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

गुजरात में प्रदूषण

220. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के प्रमुख शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शहरों में प्रदूषण रोकने के लिए पहले से चलाई जा रही प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं पर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रदूषण को रोकने में अब तक कितनी सफलता मिली है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और